

अस-अवय की पूर्व-अवयानी
किना बाक द्वारा भेजे जाने
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
भोपाल-505/अवयु. पी.



पजी क्रमांक भोपाल द्विबीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 284]

भोपाल, बुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 1990— भाद्र 9 शके 1912

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1990

अस-अवय-1-90.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (राजपत्रित) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990

2. परि-
सर्वर — इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार;
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (ग) "परीक्षा" से से अभिप्रेत है प्रतियोगी परीक्षा को सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत ली जाती है;
- (घ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का मूल जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ङ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का मूल जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (च) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित सेवा);
- (छ) "उपकालाग" से अभिप्रेत है :-

1967

(1) अंधे वे व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हों,—

- (1) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो।
 - (2) बेहतर आँसू में परिधाधी लेस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सेलन) से अधिक न हो, और
 - (3) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या वह उससे भी बढ़कर हो।
- (ii) बहुरे बहु व्यक्ति हैं जिनमें श्रवण संवेदना जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए क्रियाहीन हो, यहाँ तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते, उस प्रवर्ग में सम्मिलित किये गये वे व्यक्ति होंगे जिनमें सुनने का ह्रास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कर्ना) हो या दोनों कानों में सुनने का पूरा ह्रास हो।
- (iii) विकृतता से विकलांग वे व्यक्ति हैं जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो जिससे श्रवण, यास पेशियों या जोड़ों की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुँचती हो।

3. विस्तार तथा लागू होना :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न दृष्टियत में धारण कर रहे हों;
- (2) आपाती तथा तदर्थ आधार पर नियुक्तियों को छोड़कर वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों।

5. बर्गीकरण, वेतनमान आदि :—सेवा का बर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगा :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कमी कर सकेगी।

6. भरती का तरीका :— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से अर्थात् :—

- (क) प्रतिवोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती द्वारा;
- (ख) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल हैसियत में धारण किये हों जैसा कि अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ग) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (घ) सरकार द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात् नियम-14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आभेदन द्वारा और

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में यथा-एक में यथा-विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भरती की किसी भी विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान भरती जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा अधिसूचित से अवधारित की जावेगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की अर्थात् अनुसूची-एक में उक्त उपनियम हुए ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्ण सहमति से

में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें।

7. सेवा में नियुक्ति :- इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. गैरी भरती की पात्रता की शर्त :- परीक्षा में भाग लेने/चयन किए जाने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :-

- (एक) आयु- (क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु ऐसी आयु प्राप्त न की हो, जो कि उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट की गई है;
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु की उच्चतर सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियासत आपाती नियुक्ति के शिक्षकों, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छूटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक वर्ष से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- पद "छूटनी किए गए सरकारी सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्याया आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- पद "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की लगातार कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्याया आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छूटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आऊट कन्सेशन के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो, और जिन्हें :-

- (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) भरती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,
सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी।

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी सविदा के पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये हों, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्रम सैनिक बन योग्य नहीं रहे।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लगने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।

(घ) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट होगी।

(ड) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(छ) आदिम जाति हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जाति विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ज) विक्रम पुरस्कार धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(झ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नानकमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक, जो कि 8 वर्ष की सीमा के अधःधीन होगी, छूट दी जायेगी किन्तु किसी भी मामले में उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियासतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जबकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा देने के पूर्व या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें छटनी किया गया हो।

किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं :- उसके पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं :

परन्तु-

(क) आपवादिक मामलों में आयोग सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इस सख में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित

(क) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या प्रिन्सिपल या क्रीडा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो जो राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकारित की जाएं।

(ख) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिसकी नियुक्ति पंचायतिथि, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है।

(ग) (अ) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिस पद पर वह सरकार द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था।

(ब) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर आमंत्रित किए जाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह आवश्यक होगा कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापक अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हो। स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर आमंत्रित के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(घ) इस नियम के उपबंधों के अनुसार विचार करने के पश्चात् स्पींगिंग समिति सरकार को उपयुक्त सिफारिश करेगी, सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें अनुमोदित किए जाने के पश्चात् संबंधित व्यक्तियों के आमंत्रण के आदेश समिति की सिफारिशों के अनुसार जारी किए जाएंगे।

(च) किसी विशिष्ट पद पर आमंत्रित व्यक्ति को ज्येष्ठता उस शारीर से दी जाएगी जिसको कि महाविद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया गया था।

(छ) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमंत्रण पर कोई अवकाश अग्रणीत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, तथापि अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश लेता अभिवाच का सुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणीत करने हेतु मध्यप्रदेश अवकाश में विहित निर्बन्धनों तथा अधिकतम सीमाओं को असीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

(झ) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमंत्रित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा में उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(ञ) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सबैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।

(ज) सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्याप, सहायक प्राध्यापक, प्रिन्सिपल तथा क्रीडा अधिकारी, जिनकी नियुक्ति पंचायतिथि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी किन्तु जिन्हें स्पींगिंग समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमंत्रित किए जाने हेतु अग्रणीत किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित कि थे, तदर्थ और स्थायी आधार पर समाप्त होने वाली काठर (काठर काठर) के रूप में बने रहने, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में ज्येष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतनवृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ नहीं मिलेंगे।

में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः सात गुना तक सीमित रहेंगे ;

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो समिति क्षेत्र का विस्तार उस सीमा तक जहां तक कि यह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए कर सकेगी।

18. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना :- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम-14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तर के लिए उपयुक्त समझती है यह सूची चयन सूची तैयार करने की शारीर से एक वर्ष के दौरान सेवा नियुक्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रस्तावित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के की संख्या 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन ज्येष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए सभी दृष्टि से गुणागुण तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, ऐसी चयन सूची तैयार करते समय अनुसूची चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ;

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में आपवादिक रूप से गुणागुण वाला तथा उपयुक्त हो, सूची में उससे ज्येष्ठ अधिकारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन लोगों के ऊपर ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा, जिन पर परंपरासूचक चयन में विचार किया गया है।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जावेगा।

(5) यदि चयन पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाए कि राज्य अधिनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिकरण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिकरण के संबंध में अपने कारणों को अनिलेखबद्ध करेगी।

19. आयोग से परामर्श :- विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि सिविल सेवा के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पुश्क से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

20. चयन सूची :- (1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कालम- (2) में दर्शाए गए पदों से उक्त अनुसूची के कालम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 18 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधि-मान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की शारीर से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जावेगी ;

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर झूठ होने की दशा में सरकार की प्रेरणा पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग यदि यह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन-सूची से हटा सकेगा।

अनुसूची-एक
(नियम 4 तथा 5 देखिये)

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	आधुनिक, उच्च शिक्षा	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 5900-200-6700.
2	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	68	प्रथम श्रेणी	रुपये 4500-150-5700-200-7300.
3	प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्यक अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	347	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700-125-4950-150-5700 तथा रुपये 250/- विशेष वेतन.
4	प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	915	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700-125-4950-150-5700.
5	(अ) सहायक प्राध्यापक	7426	द्वितीय श्रेणी	रुपये 2200-75-2800-100-4000.
	(आ) सहायक प्राध्यापक (ज्येष्ठ वेतनमान)	..	प्रथम श्रेणी	रुपये 3000-100-3500-125-5000.
	(इ) सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी)	8	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700-125-4950-150-5700.
6	(अ) क्रीडा अधिकारी	324	द्वितीय श्रेणी	रुपये 2200-75-2800-100-4000.
	(आ) क्रीडा अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)	..	प्रथम श्रेणी	रुपये 3000-100-3500-125-5000.
	(इ) क्रीडा अधिकारी (प्रवर श्रेणी)	..	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700-125-4950-150-5700.
7	(अ) ग्रंथपाल	384	द्वितीय श्रेणी	रुपये 2200-75-2800-100-4000.
	(आ) ग्रंथपाल (ज्येष्ठ वेतनमान)	..	प्रथम श्रेणी	रुपये 3000-100-3500-125-5000.
	(इ) ग्रंथपाल (प्रवर श्रेणी)	..	प्रथम श्रेणी	रुपये 3700-125-4950-150-5700.

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कार्य पदों को कुल संख्या	अपने पदों को कुल संख्या	सर्वोच्च पदों को कुल संख्या	अपने पदों को कुल संख्या	अपने पदों को कुल संख्या	अपने पदों को कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
उच्च शिक्षा विभाग	मध्यप्रदेश शैक्षणिक (राजकीय) सेवा	(एक) आधुनिक, उच्च शिक्षा	1
		(दो) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	77	100 प्रतिशत
		(तीन) प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्यक अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	347	100 प्रतिशत
		(चार) (अ) प्राध्यापक और उप-संचालक, उच्च शिक्षा	915	100 प्रतिशत

अपने पदों को कुल संख्या के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के अधिकारी की प्राप्तिपूर्वक से.

राज्य सम्यक अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के कार में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना में 7 वर्ष के कार्य का अनुभव हो.

प्राध्यापक के मानन द्वारा लोकतंत्र (सिस्टमेटिक) कृत पर सीधी भरती में अथवा विशेष रुकने अतिरिक्त 1-1-86 से अथवा विशेष प्राप्तिपूर्वक से कम से कम 55 वर्ष तथा पुस्तकालय विभाग में स्नातक कृत प्राचार्य का प्रतिशत 50 से

विभागीय परदेन्ति समिति के सदस्यों के नाम पूरी तरह के परपार तथा विहित अधिनियम रखने पर सेवा रिक्त के आधार पर की जाती

ये पर विभागीय परदेन्ति समिति के माध्यम में करे जायेगे. प्रत्यापकों के ऐसे पदों की कोई निगदित संख्या नहीं होगी और इन पदों को सख्या कोषित ज्येष्ठता और अधिनियमि सहायक प्रत्यापकों को सख्या के आधार पर बरतनी रहेगी.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(बि) कायम 7 के अनुसार पदों की अनिश्चित संख्या के लिए

100 प्रतिशत

(पि) सहायक प्रत्यापक 7426
(ख) ज्येष्ठ अधिकारी 90 प्रतिशत
(सा) प्रयाग 384 10 प्रतिशत

(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा इनमें सहायक व्ययर्थियों का संवाकार भी किया जायेगा.

(2) केवल मुक्त कारर (शिरस केर) के सहायक ज्येष्ठ अधिकारों तथा सहायक प्रयाग के लिए इन अधिकारियों की परदेन्ति के परपार संविक्य में ये पर परदेन्ति से नहीं करे जायेगी.

टी. - अनुभवक (पि), (ख) एवं (सा) में उल्लिखित पदों के ज्येष्ठ और प्रार श्रेणी के वेतनमानों में प्रतियोगियों की प्रतियोगिता-वार में दिए गए दिखनी के अनुसार होगी.

अनुसूची-टी
(भाग 8 अर्धी)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पर का नाम	सूचना संख्या सीमा	उम्मीदवार संख्या सीमा	विहित शैक्षणिक अधिनियम	दिखनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. (क) प्रत्येक सी. टाए साय-समय पर विहित शैक्षणिक अधिनियम, तथा (ख) स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव

2. उल्लिखित विषय में बरतना राज्य ज्ञान टाए अध्याप के परामर्श से सिस्टि किसी अन्य विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्ती का प्रतिशत 50 से कम न रहे

3. व्यापक शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और व्यापक शिक्षा में स्नातक स्तर पर कुल प्राप्ती का प्रतिशत 50 से कम न रहे.

4. प्रत्येक विभाग में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्ती का प्रतिशत 50 से कम न रहे

परपार प्रतिशत एवं सहायक उपाधि पर परपार संख्या इन में उल्लिखित विभागीय

45 वर्ष

21 वर्ष

(क) प्रत्यापक और उप-सहायक, उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा

30 वर्ष

21 वर्ष

(ख) सहायक प्रत्यापक

उच्च शिक्षा

30 वर्ष

21 वर्ष

(क) ज्येष्ठ अधिकारी

उच्च शिक्षा

30 वर्ष

21 वर्ष

(ख) प्रयाग

उच्च शिक्षा

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 1990

1981

समुद्र तल से ऊपर
गिरा 15 फीट

प्रदेश के लिए सर्वोच्च अक्षांश सिस्टम

विषय का नाम	व्यवस्थापक का नाम जिसके अधीन की जाती है	उपरोक्त का नाम जिस पर अधीन की जाती है	(2)	(3)	(4)	(5)
रकम शिक्षा विभाग	मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (नियंत्रित/आवृत्ति सेवा)	गुजरा, माताकांठ मही, विद्यालय तथा शैक्षणिक सेवाएँ, उच्च शिक्षा	(1) प्रभात ज्योति मही-विद्यालय, मुंगठा	(2) मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा	(3) गुजरा, माताकांठ मही, विद्यालय तथा शैक्षणिक सेवाएँ, उच्च शिक्षा	(4) (1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/अधीनस्थ, उच्च शिक्षा (3) अधीनस्थ, उच्च शिक्षा-सहायक
व्यवस्थापक का नाम	व्यवस्थापक का नाम जिसके अधीन की जाती है	व्यवस्थापक का नाम जिस पर अधीन की जाती है	(1) प्रभात ज्योति मही-विद्यालय, मुंगठा सहायक तथा राज्य सार्विक अधिकारी, राठौर में सेवा लेवना.	(2) प्रभावक तथा उच्च शिक्षा विभाग	(3) गुजरा, माताकांठ मही, विद्यालय तथा शैक्षणिक सेवाएँ, उच्च शिक्षा	(4) (1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/अधीनस्थ, उच्च शिक्षा (3) अधीनस्थ, उच्च शिक्षा-सहायक

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 1990

1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निर्वाचक निर्वाचक के विभाजक के अलावा पर रखाई जाती है। कार्यभार प्रारंभ किए गए महाविद्यालयों के अनधिकृत प्राध्यापकों को सीधी भती के प्राध्यापकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें जोड़कर उनके महाविद्यालय के कार्यभार सकार द्वारा शुरू कि जाये के दिनांक से ही चलाए। सीधी भती के प्राध्यापकों को जोड़कर लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में हमारे जोड़े जोड़कर काम के अलावा पर अध्यापक की जाती है।		(3) सहकारी प्राध्यापक प्राध्यापक/उच्च सहायक, उच्च शिक्षा		(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/अधीनस्थ, उच्च शिक्षा (3) अधीनस्थ, उच्च शिक्षा-सहायक
				(4) जोड़कर लेवना में 8 वर्ष की सेवा पूर्व कर की हो परंतु सहकारी प्राध्यापक पर पर काम से कम 16 वर्ष, पीएचडी/एच डिग्री प्राप्त के दिनांक 13/15 वर्ष की सेवा पूर्व कर से है। सहकारी प्राध्यापक के संवर् में 8 वर्ष सेवा की ओका गिनत की जाएगी। (5) पीएचडी, उपाधि प्राप्त करती हो अथवा इसके समकक्ष प्रमाणित कार्य किया हो। (6) विद्वता और जोड़ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया हो, जो सहकारी प्राध्यापक, निर्देशक, प्रबंधक को उपलब्ध, निर्देशक, निर्देशक तथा पाठ्यक्रम से प्रभावित हो। (7) जोड़कर लेवना में परवहन के उपरि लेवना 5 रुपए की प्रत्येक की अवधि के अंत में प्राध्यापक पाठ्यक्रम/पीछकीन संस्थाओं में भाग लेना हो या वह, विभाजक अर्थात् अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट

वह विषयविद्यालय अनुदान आयोग

(1) (2) (3) (4) (5)

मानकों के अनुरूप समुचित अनवरत शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो, और (क) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर अच्छी हो।

- (4) सहायक ग्रंथपाल ग्रंथपाल तदर्थ
- (5) सहायक क्रीडा अधिकारी क्रीडा अधिकारी जिन्होंने क्रीडा अधिकारी के लिये निर्धारित अर्हताएं प्राप्त कर ली हों, सेवा रिकार्ड के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे। तदर्थ

टिप्पणी :- सहायक ग्रंथपाल एवं सहायक क्रीडा अधिकारी के पद समाप्त होने वाले कारर (डाईंग कैरर) के हैं, अतः वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की उपर्युक्तानुसार पदोन्नति के पश्चात् अविद्य में ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों पर पदोन्नतियां नहीं होगी।

टिप्पणी :- (1) सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्न अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा :-

(अ) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु :- सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी को रु. 3000-5000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जावेगा यदि उसने (एक) नियमित नियुक्ति के उपरान्त 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि वह पीएचडी, अथवा एम. फिल, धारक हो तो क्रमशः 5 तथा 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (दो) दो पुनर्षुच्य पाठ्यक्रमों/प्रीव्यकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या अन्य समुचित अनवरत शिक्षण कार्यक्रमों में सलगन रहा हो, जो गुणवत्ता में विषयविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के समकक्ष हो, (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर सतोषजनक हो, (ब) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु :- ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत प्रत्येक सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल को रु. 3700-5700 के प्रवर श्रेणी के वेतनमान में रखे जाने की पात्रता होगी, यदि उसने :- (एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रंथपाल के पद पर कम से कम 16 वर्ष पीएचडी/एम. फिल. धारक के लिये क्रमशः 13/15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले अधिकारियों के संवध में 8 वर्ष की शर्त को विधिल किया जाएगा तथा (दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरान्त दो पुनर्षुच्य पाठ्यक्रम/प्रीव्यकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का है भाग लिया हो या वह विषयविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अनवरत शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो और (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर सतोषजनक हो।

निराकरण के लिए

(2) उक्त वेतन का प्रारंभिक वेतन में जो जाने की उपस्थिति अर्थात् करने के लिए एक कर्मचारी कर्मिणी में विना कर रहे हैं।

- (4) अनुपस्थिति, उक्त वेतन या उक्त वेतन नाम निर्दिष्ट करने की कर्मिणी संचालक
- (5) उक्त वेतन, प्र. शा. शा. शा. उक्त वेतन निर्दिष्ट
- (6) प्रारंभिक वेतन/वेतन/वेतन/वेतन के प्रारंभ (उक्त वेतन वेतन नाम निर्दिष्ट)
- (7) उक्त वेतन में कर्मिणी एक निर्दिष्ट

कर्मिणी कर्मिणी रूपी में जो जाने की उपस्थिति अर्थात् करने हेतु समय-समय पर प्रकाश करा जाते हैं। जो कर्मिणी के अनुसार कर्मिणी का प्रकाश करा जाते हैं।

(3) प्रत्येक प्रकाशक और प्र. शा. में प्रतीति लिए प्र. शा. प्रकाशक का एक एक है।

अनुसूची-पांच

[नियम 14 (ख) देखिए]

आवेदन-पत्र का प्रोफार्मा

फोटो पासपोर्ट साइज (अनुप्रमाणित)

(महायुक्त प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/ग्रहपाल पद हेतु)

1. नाम तथा पता विवरण
2. राज्य का नाम जहां जन्म हुआ
3. जन्म तारीख (अको में) दिन
(शब्दों में)
4. (पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में) को आयु
वर्ष माह दिन

5. शैक्षणिक अर्हताएं :-

महल/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विवरण	प्राप्तांक/पूजांक
अ. हायर सेकेण्डरी				
ब. स्नातक				
क. स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अनुसूची की अनुप्रमाणित प्रति अर्पित है

6. यदि एम. फिल/पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का नाम कथित करें तथा प्रमाण-प्रस्तुत करें
7. यदि अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. का सदस्य है, तो जाति तथा जनजाति का नाम दिया जाना चाहिए, सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र सलग्न करें.
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम तथा संस्था का नाम, विभाग का नाम दर्शित करें.
9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो.

तारीख अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
स्थान मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 1990

क्र. 3257-अइतीस-1-90.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3256-अइतीस-1-90, दिनांक 31 अगस्त 1990 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, सचिव.

6. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by competitive examination/selection;
- (b) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such service as specified in Schedule-II;
- (c) by promotion of members of the service as specified in column (2) of Schedule-IV.
- (d) by absorption in accordance of the procedure prescribed in rule 14, after the taken over of any college by the Government; and

(2) The number of persons recruited under clause (b) of clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period or recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with prior concurrence of the Personnel Administrative Reform and Training Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility of direct recruits.—In order to be eligible to compete at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(i) **Age.**—(a) The candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule III and not attained the age as specified in column (5) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the teachers appointed on emergency basis, contingency paid employees, Workcharged employees and employees working in the Project Implementation Committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant, age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Bhopal, the 31st August 1990

No.3256-XXXVIII-1-90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Higher Education Department (Gazetted) Service, namely:—

RULES

1. Short Title.—These rules may be called the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990.

2. Definitions.—In these rules, unless the context other requires,—

- (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;
- (d) "Scheduled Caste" means any caste, race of tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (e) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (f) "Service" means the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Gazetted, Service;
- (g) "Physically handicapped" means:—

(I) "A person is blind if he suffers from one of the following conditions,—

- (i) Total loss of vision;
- (ii) intensity of eye sight is not more than 6/60 or 20/200 (shellan) in the better eye with the corrective lens or
- (iii) the frontal angle of vision is limited to an angle of 20° or less.

(II) A person is deaf if he lacks sensation of hearing required for daily purpose, to the extent that he cannot hear or understand even amplified sound. Such persons who suffer from loss of hearing of the better ear to the extent of more than 80 decibals (maximum loss) or who have lost the sense of hearing in both ears will be included in this category.

(III) Those persons will be deemed to be suffering from the physical infirmity who have a physical defect or deformity which does not allow the bones, muscles or joints in normal bodily functions.

3. Scope and application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely:—

- (1) persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I
- (2) persons recruited to the Service except on emergency and adhoc basis before the commencement of these rules; and
- (3) persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classifications, scale of pay, etc.—The classification of the Service the number of posts included in the Service and the Scale of Pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the Service either in a permanent or temporary basis.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.
 - (2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short-term engagement (b) fulfilling the conditions of enrolment.
 - (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers).
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
 - (6) Ex-Servicemen invalided out of service.
 - (7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
 - (8) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidate who are employee of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
- (e) The general upper age limit shall be 35 years in respect of widow destitute and divorced women candidates.
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 years in respect of those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare Programme.
- (g) The general upper age limit shall be relaxed upto 5 years in respect of awarded superior cast partner of a couple under the Inter Caste Marriage incentive programme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.
- (h) The upper age limit shall also be relaxed upto 5 years in respect of "Vikram Award" holders candidates.
- (i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note.—Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination.

(ii) **Educational Qualification.**—He must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III:

Provided that.—

- (a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination/selection;
 - (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for the examination/selection at the discretion of the Commission.
- (iii) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Commission.

(E) No person appointed as or holding the post of a Registrar, or a Librarian or a Sports Officer, in a non-government college taken over by the State Government, shall be absorbed in Government Service, unless at the time of appointment, such person answers such minimum requirements or holds such qualifications as may be laid down by the State Government by an order in writing.

(F) No person shall be absorbed in Government Service whose appointment is not approved as a regular appointment by Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or the University as the case may be.

(iii) (A) No person shall be absorbed in a higher post in Government Service from the post on which he was working prior to the take over of the college by Government.

(B) for being absorbed as Principal of a Degree College, a person working as Principal of a college taken over by Government shall, in addition to the other conditions prescribed under this Rule have a minimum of 14 years teaching experience out of which 3 years teaching experience shall pertain to teaching of post graduate classes and two years teaching experience as a Professor, for absorption to the post of Principal Post graduate College, a further experience of two years of working as a Principal of a Degree College shall be necessary.

(iv) The Screening Committee, after taking into consideration the relevant provisions of this rule shall make suitable recommendations to Government. After the recommendations of the Committee are approved by Government, the absorption orders of the concerning persons will be issued by Government according to the recommendations of the Committee.

(v) A person absorbed to a particular post shall get his seniority from the date the college was taken over.

(vi) No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a non-government college on his absorption in Government service. However, if such a person pays the leave salary contribution in respect of the service rendered in a non-government college, he shall be permitted to carry forward the leave so earned subject to the restrictions and maximum limits prescribed in the Madhya Pradesh Leave Rules.

(vii) No person absorbed into Government service under the provision of this Rule shall by virtue of the fact that he was earlier confirmed in service by the non-government college claim as of right to be confirmed in Government service. Confirmation of such persons shall be done in accordance with the Government rules in force from time to time.

(viii) The provisions of these rules shall be and shall always be deemed to have come into force with effect from the 1st January 1971.

(ix) The Principal, Professor, Asst. Professor, Librarian and Sports Officer of the non-government college, taken over by the Government whose appointments were approved as a regular appointment by Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or the University, as the case may be, but are rejected by the Screening Committee for their absorption in Government Service due to any reason, will continue on the post, they held on adhoc and temporary basis in dying cadre, but will not get any benefit of seniority, promotion, annual increments and revision of pay-scale in Government Service as such.

Emergency Appointment.—If commission's panel of selected candidates is not available for the post of Asstt. Sports Officers, the posts may be filled by emergency appointments in the following manner:—

- (A) An advertisement shall be issued by the Government.
- (B) For Emergency appointments to the post of Asstt. Professor, Librarian and Sports Officers the educational qualifications will be the same as shown in Schedule-III for these posts.
- (C) Application for emergency appointment shall be submitted in the form prescribed in Schedule -V.
- (D) Application received shall be registered and tabulated according to the following norms in order of merit:—
 - (i) Percentage of the Marks obtained at Degree level shall be the basis of allotment of marks out of 40 marks.
 - (ii) Percentage of marks obtained at Post Graduate level shall be the basis of allotment of marks out of 50 marks.

9. Disqualification.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission/election to the examination.

10. Commission's Decision about the Eligibility of Candidates Final.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission.

Shall be admitted to the examination or interviewed by the Commission.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination.—(1) Direct recruitment shall be made by competitive examination to the posts of Assistant Professor, Librarian and sports officer and the merit list shall be made for the appointment on the basis of total marks obtained in written examination and interview.

(2) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission from time to time determine. The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issued in consultation with the Commission.

(3) 15 per cent and 18 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively. In addition to this, three per cent of the available vacancies shall be reserved for those physically handicapped whose deformity does not become hurdle in teaching work.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are physically handicapped, members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes recommended by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance or efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forwarded) shall not at any time exceed forty five per cent of the total vacancies advertised.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of public service commission or any other competent authority it is found that the sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the public service commission or the competent authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates.

12. Direct Recruitment by Selection.—(1) Direct recruitment for the post of Professor by the commission shall be made through interview. Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the commission from time to time determine. If the number of available candidates is too much than the vacant posts, the commission may limit the number of candidates calling for interview on the basis of higher educational qualifications or experience or both.

(2) 15 per cent and 18 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and selected by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(5) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies shall be reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates, if even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (including the vacancies carried forwarded) shall not at any time exceed 45 per cent of the total vacancies advertised.

13. List of Candidates recommended by the Commission.—(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the category of disabled, Scheduled Caste and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Commission. Provided that the Government with the consultation of the Commission may extend the validity of the select list upto a maximum period of one more year.

14. Recruitment by Absorption.—(1) The absorption of Principals, Professors, Asst. Professors Librarian and Sports Officers of non-government college taken over by the Government will be made through Screening Committee, after examining every case and on its recommendations to the Government. The Committee shall be comprising of the following members:—

- (a) Chairman, Public Service Commission or a member of the Commission, nominated by the Chairman.
- (b) Principal Secretary/Secretary, Higher Education.
- (c) Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh.
- (d) Two Principals of Government Post Graduate Colleges, nominated by the Government.

(ii) The Screening Committee shall recommend the cases referred to it for absorption to appropriate posts on the following basis:—

- (A) All these persons, who were recruited as a regular appointee in the private colleges taken over by the Government according to the provisions given in the college code of the concerning universities prior to the commencement of the Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Act.
- (B) No such person shall be absorbed who is recruited after the commencement of the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1967 and does not fulfill the minimum requirements prescribed in the said rules.
- (C) No person shall be absorbed if at any time in the past he or she was removed or dismissed from Government or any other service for proved misconduct and/or criminal offence.
- (D) No person shall be absorbed in Government Service if he or she has attained the age of superannuation according to the Government rules in force at the time of absorption.

(iii) 5 marks for M. Phil degree and;

(iv) 5 marks for Ph. D. Degree.

A merit list prepared subjectwise in the above manner shall be used for the filling the available vacancies in the serial order for the emergency appointments. However, all such candidates appointed on the emergency basis shall be subject to the condition, that their services will be terminated as soon as a selection list prepared by Public Service Commission is received.

16. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 15% and 18% of the available vacancies for promotion in such posts in which the percentage of promotion is 33.5 percent or more, as specified in Schedule-II, shall be reserved for officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 17.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administration Department from time to time.

17. Conditions of eligibility for promotion/transfer.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year had completed such number of year of service (Whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the services of the released officers of the Emergency Commission and short service commission after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with the General Administrative Department Memo No. 2266/1987/1(3)/67 dated the 21st October 1967.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of posts filled on the basis of merit-cum-seniority:

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

18. Preparation of list of suitable officers.—(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the Service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list:

Provided that any junior officer, who in the opinion of the Committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation.—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any number of the State Subordinate Civil Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

19. **Consultation with the Commission.**—The recommendations of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of Clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

20. **Select List.**—(1) The list as finally approved by the Government shall form the Select List for promotion of the members of the service to post shown in column (3) of Schedule-IV from column (2) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 18, but the validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any persons included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, may if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

21. **Appointment to the Service from the Select List.**—(1) Appointment of the Officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the Select List:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

22. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

23. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

24. **Relaxation.**—Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

25. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time to this regard.

26. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
YOGENDRA NATH CHATURVEDI, Secy.

SCHEDULE I
(See Rule 4 and 5)

S. No.	Name of Post included in the service	Number of posts.	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Commissioner, Higher education	1	Class-I	5900—200—6700
2	Principal, P. G. College and Additional Director Higher Education	68	Class-I	4500—15—5700—200—7300
3	Principals Degree College Joint Director, Higher Education and State Liaison Officer (N. S. S.)	347	Class-I	3700—125—4950—150—5700— Rs. 250/-Special Pay.
4	Professors and Deputy Director Higher Education	913	Class-I	3700—125—4950—150—5700
5	(A) Asstt. Professor	7426	Class-II	2200—75—2800—100—4000
	(B) Asstt. Professor (Senior Scale)	..	Class-I	3000—100—3500—125—5000
	(C) Asstt. Professor (Selection Grade)	8	Class-I	3700—125—4950—150—5700
6	(A) Sports Officer	324	Class-II	2200—75—2800—100—4000
	(B) Sports Officer (Senior Scale)	..	Class-I	3000—100—3500—125—5000
	(C) Sports Officer (Selection Grade)	..	Class-I	3700—125—4950—150—5700
7	(A) Librarian	384	Class-II	2200—75—2800—100—4000
	(B) Librarian (Senior Scale)	..	Class-I	3000—100—3500—125—5000
	(C) Librarian (Selection Grade)	..	Class-I	3700—125—4950—150—5700

SCHEDULE II
(See Rule 6)

Name of Department	Name of Service	Name of post	Number of Duty post	Percentage of Duty post to be filled in			Remarks
				By direct Recruitment	By promotion of substantive members of service	By transfers of persons of other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Department of Higher Education	M. P. Educational (Gazetted) Service	(i) Commissioner	1	An Officer of Indian Administrative Services of Supertime Scale on deputation.
		(ii) Principal P. G College and additional Director, Higher Education.	77	..	100%
		(iii) Principal, Degree, College Joint Director, Higher Education and State Liaison Officer National Service Scheme.	347	..	100%	..	State Liaison Officer shall be from amongst the degree, Principal Cadre, having seven years experience of National Service Scheme.
		(iv) (A) Professor and Dy. Director, Higher Education.	915	100%	Direct Recruitment shall be made on total number of substantive posts of professors sanctioned by Govt. In addition to this on account of enforcement of new U.G.C. Pay-Scales from 1-1-86. Promotion to the post of professors shall be made on the basis of service record from amongst the Asstt. Professors of senior/selection grade pay-scale after completion of prescribed period of service and prescribed qualification under provisions mentioned in in Schedule-IV. These posts shall be filled up through departmental promotion committee. No definite number of these posts of professors shall be and member of these posts will
		(B) For uncertain number of posts according to column (7).					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(v) Asst. Professor	7426	100%*			
		(vi) Sports Officer	324	90%*	10%**		
		(vii) Librarian	384	90%*	10%**		
							*By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well.
							**Only for assistant librarian of dying cadre, these posts shall not be filled up by promotion in future after promotion of these officers.

Note.—The procedure of appointment in the senior and selection grade pay scale to the posts mentioned in serial No. (V), (VI) and (VII) shall be according to the note given in Schedule IV.

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Name of Post (3)	Minimum age of limit (4)	Upper age of limit (5)	Educational qualification prescribed (6)	Remarks (7)
Department of Higher Education	Madhya Pradesh Educational Service (Gazetted)	(i) Professors and Dy. Director Higher Education	21 years	45 years	(A) Educational qualification prescribed by U. G. C. from time to time; and (B) Ten years teaching experience of graduate/post graduate classes.	
		(ii) Asst. Professor	21 years	30 years	Post Graduate degree in relevant subject or in any other subject mentioned by the State Govt. with the advice of the Commission with atleast 55% marks and at degree level the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	
		(iii) Sports Officer	21 years	30 years	Post graduate degree in physical education with atleast 55% marks and at degree level of physical education the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	
		(iv) Librarian	21 years	30 years	Post graduate degree in Library Science with atleast 55% marks and at degree level the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	
					OR	
					Atleast 55% marks in M. A./M. Com/M.Sc. and at graduate degree in Library Science the percentage of total marks obtained should not be less than 50.	

SCHEDULE - IV
(See Rule - 15)

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Experience required for promotion	Name of members of the Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Higher Education	M. P. Educational Service (Collegiate Branch)			
	(1) Principal Degree College, Joint Director and State Liaison Officer, National Service Scheme.	Principal, Post graduate colleges and Additional Director, Higher Education.	Promotion to the post of Principal, Post graduate college, from amongst those Degree Principals having at least two years experience of the post of Principal, shall be made on the basis of combined seniority list of Principal degree college cadre. The promotion shall be on the basis of merit-cum-seniority. Provided that, the condition of experience shall not apply to persons whose name could not be considered at the time of earlier promotions despite having seniority.	(1) Chairman, Public Service Commission or any member nominated by him— Chairman Secretary, Higher Education— Member (2) Principal Secy./ Secretary, Higher Education— Member (3) Commissioner, Higher Education— Member.
	(2) Professor and Deputy Director, Higher Education.	Principal, Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liaison Officer, National Service Scheme.	Promotion to the post of Principal degree college shall be made on the basis of merit-cum-seniority from amongst those professors having atleast two years experience. Separate seniority list shall be prepared for directly recruited professors and promoted professors for the promotion to the post of principal, through the departmental promotion committee. The post of Principal shall be filled up from amongst these lists in such ratio which exists between the directly recruited professor and promoted professors at the commencement of the calender year of meeting of promotion committee. While enquiring about the eligibility for promotion, these shall be no distinction between the time bound professors and other professors. The seniority list of promoted professors shall be made on the basis of the date of their regular appointment to the post of assistant professor. The absorbed professors of the taken over colleges shall be enlisted with directly recruited professors and shall be granted seniority from the date from which their college has been taken over by the government. The seniority of directly recruited professor shall be determined on the basis of seniority mentioned in the selection	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				list issued by the Public Service Commission.
(3) Asstt. Professor	Professor/ Dy. Director, Higher Education			<p>Assistant Professors working in the Senior/Selection grade pay scale shall be eligible for promotion to the post of Professors in the Pay-scale of Rs. 3700-5700, if He/She has;</p> <p>(a) Completed 8 years of service in the senior scale, provided that the requirement of 8 years will be relaxed if the total service of the Asstt. Professor is not less than 16 years for Ph.D and M. Phil. holders 13 and 15 years respectively.</p> <p>(b) obtained in Ph.D degree or an equivalent published work;</p> <p>(c) made some mark in the areas of scholarship and research as evidence by self-assessment, reports of referees quality of publications, contribution to educational renovation, design of new courses and curricular, etc;</p> <p>(d) participated in two refresher courses/summer institutes each of approximately 4 weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified by the UGC, after placement in the Senior Scale; and;</p> <p>(e) Consistently good performance appraisal reports.</p>
(4) Asstt. Librarian	Librarian			Those assistant librarians who have acquired the qualification prescribed for librarian, shall be promoted on the basis of service record, to the post of librarian.
(5) Asstt. Sports Officer	Sports Officer			Those Assistant Sports Officers who have acquired the qualifications prescribed for Sports Officer shall be promoted on the basis of service record to the post of Sports Officer.

Note.—The post of Asstt. Librarian and Assistant Sports Officers, are of dying cadre. Therefore the persons working at present on these posts shall be given promotion to the post of Librarian and Sports Officer shall be made in future.

Note.—(1) The following qualifications will be essential for Asstt. Professor, Sports Officers and Librarian for their placement in senior pay -scale and selection grade pay -scale:—

(A) for Senior Pay- Scale:—Asstt. Professor/Librarian/Sports Officer will be placed in senior pay- scale of Rs. 3000-5000 if he/she has (i) completed 8 years of service after regular appointment, or completed 5 years or 7 years of service in case of Ph. D or M. Phil degree holders, respectively, (ii) participated in two refresher courses/summer institutes, each of approximately 4 weeks duration or remained associated with appropriate continuing education programmes, or comparable quality as may be specified by UGC; and (iii) consistently satisfactory performance appraisal report.

(B) for Selection Grade Pay -scale:—Every Assistant Professor/Sports Officer/Librarian working in senior pay- scale shall be eligible for placement in the Selection Grade Pay -scale 3700-5700, provided he/she (i) has completed 8 years of service in the senior scale. The condition of 8 years shall be relaxed in case of officers who have completed atleast 16 years and for Ph.D and M. Phil holders 13 and 15 years respectively of service on the post of Asstt. Professor/Sports Officer/Librarian, (ii) after posting in the senior scale has participated in two refresher courses/summer institutes each of approximately 4 weeks duration, has remained associated with appropriate continuing education programmer equivalent to standards approved by UGC; and (iii) has consistently good performance appraisal reports.

(2) The Screening Committee for determining the fitness for placement in senior scale and selection grade pay- scale and shall consist of the following members:—

(A) Commissioner, Higher Education or any additional director nominated by him.	Convener
(B) Deputy Secretary, Govt. of M. P., Higher Education Department	Member
(C) Principal Govt. Post Graduate College (Nominated by Commissioner Higher Edn.)	Member
(D) An educationist related to Higher Education.	Member

The screening committee shall perform the function of screening mentioned above for determining fitness for placement under instructions issued by the Government from time to time.

(3) The post of Assistant Professors and formerly recruited Lecturers are one and the same.

SCHEDULE - V
(See Rule 14 b)

Proforma of Application

Asstt. Professor/Sports Officer/Librarian

1. Name and Address -----

Photo
Passport size
(attested)

Subject-----

2. Name of State where born-----

3. Date of birth (In figure)-----

(In words)-----

4. Age as on 1st day of January----- (In the year of advertisement for the post)

5. Educational Qualifications.

Board/University

Year Division Subject marks/full marks

- a. Higher Secondary
- b. Graduation
- c. Post Graduation

Attested copy of marks sheet required for every stage.

6. If M. Phil./Ph.D. degree awarded name of subject -----
should be quoted and must subject proof of it. -----

7. If candidate belongs to SC/ST -----
The name of caste/tribe should be given with -----
certificate from competent authority. -----

8. If candidate is already Employed indicate the -----
name of post Name of the institution name of -----
the department. -----

9. Any other information that candidate wants -----
to submit. -----

Date:-----

Place:-----

Signature of Candidate.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
YOGENDRA NATH CHATURVEDI, Secy.

(2)

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के.नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2005—भाद्र 24, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-103/2004/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (5) में “30 वर्ष” के स्थान पर “32 वर्ष” स्थापित की जाए.
- (2) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ अथवा ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड-बी, सात बिन्दुओं सहित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय से अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि.

नोट :-यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जावेगा, जो निम्नानुसार है :-

Grade	Grade point	% Equivalent
O	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-1.49	25-34
F	0.00-0.49	0-24

(ख) उपरोक्त अंशतःओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा सहायक प्राध्यापकों के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा (NET) जिसे यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. या छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित SLET परीक्षा उत्तीर्ण किया हो."

(3) अनुसूची तीन के सरल क्र. (दो) में कॉलम (7) में निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

"(क) सहायक प्राध्यापक पद हेतु पी-एच.डी. अभ्यर्थियों को भी नेट/स्लेट की अनिवार्यता होगी, तथापि वे अभ्यर्थी जो 31 दिसम्बर, 1993 तक एम. फिल. उपाधि प्राप्त कर लिये हों अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2002 को अथवा इसके पूर्व संबंधित विषय में विश्वविद्यालय को पी-एच.डी. शोध-ग्रन्थ जमा किये हों, को नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से छूट रहेगी, किन्तु जो पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें नेट/स्लेट की अनिवार्यता होगी."

(ख) वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश स्लेट 1-1-2000 के पूर्व उत्तीर्ण किये हों वे परीक्षा हेतु पात्र होंगे."

Raipur, the 15th September 2005

NOTIFICATION

No. F 1-103/2004/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) For entries "30 year" in column (5) in serial No. (ii) of Schedule III the entries "32 years" shall be substituted.
- (2) For entries in column (6) in serial No. (ii) of Schedule III the following entries shall be substituted :—
 - (a) Good academic record with atleast 55% marks or grade of "B" in the 7 point grading system obtained at the Master's degree level in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian University or a Foreign University.

Note :—As per conversion table of the U.G.C., the percentage of marks shall be converted as follows :—

Grade	Grade point	% Equivalent
O	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-1.49	25-34
F	0.00-0.49	0-24

- (b) Besides fulfilling the above qualification candidate should have cleared the eligibility test (NET) for Asstt. Professor conducted by the U.G.C./CSIR or SLET conducted by Chhattisgarh State."
- (3) In column (7) in serial No. (ii) of Schedule III, the following shall be added :—
- "(a) NET/SLET shall remain the compulsory requirement for appointment as Asstt. Professor even for candidate having Ph. D. Degree. However, the candidate who have completed M. Phil Degree by the 31st Decembar, 1993 or have submitted Ph. D. thesis to the University on or before 31st Dec. 2002 are exempted from appearing in the NET/SLET examination. In case such candidates fail to obtain Ph. D. Degree, they shall have to pass the NET/SLET Examination.
- (b) Those candidates who have cleared M.P. SLET examination before 1-11-2000 shall be eligible for the examination."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुना, उम-सचिव.

3

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत: क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2007—श्रावण 12, शक 1929

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-49/2007/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद में 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (दो) के सामने, कालम नं. (6) (ख) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(ख) राज्य सरकार द्वारा यू. जी. सी. अथवा सी. एस. आइ. आर. अथवा सेट द्वारा संचालित पाठ्य परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण,

परंतु संबंधित विषय में पी. एच. डी. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या स्नातक अध्यापन हेतु परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट दिया जाएगा.

परंतु यह और भी कि संबंधित विषय में एम. फिल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर के अध्यापन हेतु ऐसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दिया जाएगा.”

2. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (दो) के सामने, कालम नं. (7) की प्रविष्टि का लोम किया जाये.
3. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (तीन) के सामने, कालम नं. (6) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “(1) भौतिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा खेल में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ समतुल्य डिग्री अथवा यू. जी. सी. 7 पाइंट स्केल में बी. के समतुल्य श्रेणी तथा बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड हो.
- (2) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य के प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो.
- (3) शारीरिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो.
- (4) यू. जी. सी. अथवा यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय परीक्षा में अर्ह हो.”
4. अनुसूची तीन के कालम नं. (3) की प्रविष्टि (चार) के सामने, कालम नं. (6) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “(1) यू. जी. सी. द्वारा अथवा यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्ह हो.
- (2) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ समतुल्य व्यावसायिक डिग्री अथवा यू. जी. सी. 7 पाइंट स्केल में बी. के समतुल्य श्रेणी तथा लायब्रेरी के कम्प्यूटीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड हो.”

Raipur, the 3rd August 2007

NOTIFICATION

No. F 1-49/2007/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For the entries of column No. (6) (b) against the entry (ii) of column No. (3) of Schedule III, the following shall be substituted, namely :—
- “(b) Clearance of eligibility test (NET) conducted by the UGC or CSIR or SET by the State Government.
- Provided that candidates having Ph. D degree in the concerned subject will be exempted from the clearance of such test for teaching of Post Graduate and Under Graduate.
- Provided further that candidates having M. Phil degree in the concerned subject will be exempted from clearance of such test for teaching of Under Graduate Level.”
2. The entries of column No. (7) against entry (ii) of column No. (3) of Schedule III shall be omitted.

3. For the entries of column No. (6) against entry (iii) of column No. (3) of Schedule III, the following shall be substituted, namely :—
- (1) Master's degree in Physical Education (Two years Course) or Master's degree in sports or an equivalent degree with atleast 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC 7 point scale and consistently good academic record.
 - (2) Record of representation of University/College at interuniversity/intercollegiate competitions or the State in National Championship.
 - (3) Passed the physical fitness test.
 - (4) Qualifying in the National Test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC."
4. For the entries of column No. (6) against entry (iv) of column No. (3) of Schedule III, the following shall be substituted, namely :—
- (1) Qualifying in the National level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.
 - (2) Master's degree in Library Science / Information Science / Documentation or an equivalent professional degree with atleast 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC 7 point scale and consistently good academic record, computerization of library."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिन्हा, संयुक्त सचिव.

4

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (चिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2010—ज्येष्ठ 7, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक 1973 एक 1-57/2009/38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के अतिरिक्त, इस नियम में सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट समस्त पदों के लिए, अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने की तारीख के आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो”.

परन्तु प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमाये लागू होगी.

परन्तु यह और भी कि प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, आयु सीमा में छूट के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अलावा कोई और प्रावधान भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित संशोधित तथा लागू होगा.

“परन्तु यह और भी कि सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् “अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष” के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर, दिनांक 16-09-2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होगी”.

2. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परन्तु उपरोक्त प्राबधान, प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होगा”.

3. अनुसूची-तीन में कॉलम (5) के शीर्षक “उच्चतर आयु सीमा” के अन्तर्गत, प्राध्यापक/उप संचालक, उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

1.	पुरुष अनारक्षित	-	45 वर्ष
2.	पुरुष (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	-	50 वर्ष
3.	महिला अनारक्षित	-	55 वर्ष
4.	महिला (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	-	60 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग)	-	60 वर्ष

परन्तु यह और भी कि प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी”.

Raipur the 28th May, 2010

NOTIFICATION

No. 1973/F.1-57/2009/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of sub-rule (1) of Rule 8, the following clause shall be substituted, namely :-

“ In addition to the direct recruitment to the post of professor, for all posts specified for direct recruitment in this Rule, the candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, following the issuance of Advertisement by the Commission :

Provided that for the direct recruitment to the post of professor, the age limit specified in column (5) of Schedule-III shall be applicable.

Provided further that for direct recruitment to the post of professor the provision for relaxation in age limit specified else where shall stand amended and applicable, mutatis mutandis.

Provided further that General Administration Department circular No. F. 3-2/2002/1-3, Raipur, dated 16-09-2008 restricting the “upper age limit to 45” after including all types of relaxations, shall not be applicable for direct recruitment to the post of Professors.”

2. After clause (c) of sub-rule (1) of Rule 8, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the above provision shall not be applicable for direct recruitment to the post of professors."

3. In Schedule-III, for column (5) under heading "upper age of limit" for Professors/Deputy Director, Higher Education, the following entries shall be substituted, namely :-

1.	Male Unreserved	-	45 Years.
2.	Male (Reserved Category- Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Other Backward Classes)	-	50 Years.
3.	Female Unreserved	-	55 Years
4.	Female (Reserved Category-Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes)	-	60 Years
5.	Widow, destitute, divorcee (Reserved/Unreserved Category).	-	60 Years.

Provided further that for direct recruitment to the post of professor, after availing of various age relaxations specified in the rule, the upper age limit shall not exceed 60 years."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राजव, प्रमुख सचिव.